with dual tariff rates for normal and peak hours; and

(b) if so, by when this reform is being introduced?

THE MINISTER OF POWER (SHRI R. KUMARAMANGALAM) (a) No. Sir. Under the provision of Electricity (Supply) Act, 1948 State Governments/ SEBs are empowered to fix electricity tariff applicable to the retail consumers.

(b) As per information available, States like West Bengal, Kerala, Tamil Nadu, Goa & Gujarat have introduced dual tariff rates for industrial consumers provided with TOD meters.

Demand and supply of Power in Delhi

1599. SHRIMATI KAMLA SINHA:
SHRI WASIM AHMAD:

Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) the overall power supply position in the city of Delhi as against the demand;

(b) the overall rise in the demand for power during 1997 and the extent to which the power supply was augmented to meet the demand during the year; and

(c) what efforts have been made by Government to agument the power supply to solve the city's power problem?

THE MINISTER OF POWER (SHRI R. KUMARAMANGALAM) (a) The actual power supply in Delhi during March, 1998 to May, 1998 is as follows:—

ENERGY (MU)

Month	Requirement	Availability	Shortage	%
March, 98	1140	1113	27	2.4
April, 98	1290	1271	19	1.5
May, 98	1505	1439	66	4.4

PEAK (MU)

Month	Requirement	Availability	Shortage	%
March, 98	2090	2086	04	0.2
April, 98	2343	2151	192	8.2
May, 98	2545	2258	287	11.3

(b) During the year 1997-98, the peak demand for power has risen to 2450 MW as compared to 2230 MW during the year 1996-97.

(c) Thus there was an increase of 9.9% in the peak demand for power. As against thus, the demand met has risen to 2283 MW as compared to 2073 MW during the year 1996-97 registering a growth of 10.1%.

(c) In order to improve the power availability in Delhi following measures have been taken:

(i) DVB has been allocated 25% (200 MW) of unallocated quota in Central Sector stations to meet its summer-requirements.

(ii) DVB is being assisted from Northern Grid to meet its peak demand over and above its entitlement.

(iii) powergrid is installing shunt capacitors at DVB's sub-stations on war-footing to improve voltage in Delhi as low voltage is a major problem of Delhi resulting in reduction of generation at the power stations.

(iv) DVB has been advised to improve generation of its generating stations

(v) Power Grid has taken over operation and maintenance of three grid Sub-Stations of DVB.

State-wise Demand and Supply of Power

1600. SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI:
SHRI E. BALANANDAN:

Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) the State-wise demand and supply of power in the country during the 8th plan period; and

(b) Government's assistance to the States, State-wise?

THE MINISTER OF POWER (SHRI R. KUMARAMANGALAM) (a) State-wise power supply position during the various years of 8th Plan is given in Annexure-I. [*See* Appendix 184, Annexure No. 52.]

(b) State-wise entitlement vis-a-vis actual drawal from Central Sector Stations during the 8th Plan period is given in Annexure-II [*See* Appendix 184, Annexure No. 52.]

बांका में एक ग्रिड स्टेशन बनाया जाना

1601. **श्री जनार्दन यादव:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बांका (बिहार) में एक ग्रिड स्टेशन बनाने की स्वीकृति 1985 में दी गयी थी;

(ख) क्या यह सच है कि बांका ग्रिड स्टेशन का आधे से अधिक कार्य पूरा हो गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिये अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है; और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

विद्युत मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) से (घ) बांका (बिहार) में 2×20 एमवीए 132/33 के०वी० उपकेन्द्र की स्थापना हेतु एक परियोजना को बिहार राज्य बिजली बोर्ड ने 1985 में 42.53 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर स्वीकृत किया था। इस परियोजना की संशोधित लागत 600 लाख रुपये है। बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, लगभग 50% कार्य पूरा कर लिया गया है। इस उपकेन्द्र को अक्तूबर, 1999 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

विद्युत क्षेत्र का विकास

1602. **श्री ईश दत्त यादव:**
चौधरी हरमोहन सिंह यादव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विद्युत के विकास हेतु बाहरी देशों एवं विदेशी संस्थाओं से कोई सहायता मिली है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष का योजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की तारीख तक योजना-वार कितने प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है?

विद्युत मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनों के योजना-वार ब्यौरे और बाह्य सहायता का संचयी समुपयोजन दर्शाने वाला विवरण अनुपत्र में संलग्न है जो कि परियोजना द्वारा प्राप्त की गई प्रगति का स्पष्ट सूचक है। [देखिए परिशिष्ट 184, अनुपत्र सं० —53]

विद्युत वित्त निगम का कार्य-निष्पादन

1603. **श्री ईश दत्त यादव:**
चौधरी हरमोहन सिंह यादव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्युत वित्त निगम के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन गंभीरतापूर्वक नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि मूल्यांकन किया गया है, तो उक्त मूल्यांकन के आधार पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

विद्युत मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम):

(क) से (ग) पावर फाइनेंस कार्पोरेशन (पीएफसी) विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान है। निगम वर्ष 1993-94 से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करता रहा है और इसका मूल्यांकन प्रति वर्ष सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा किया जाता है। पीएफसी समझौता ज्ञापनों में निर्धारित लक्ष्यों के प्रति अच्छा कार्य निष्पादन कर रही है और वर्ष 1993-94 के बाद से उत्कृष्ट दर्जा हासिल करती रही है। निगम के